on the other hand attract basic plus auxiliary customs duty at 80 per cent. Thus, at present, generally the rate of import duty on raw materials for the electronic industry (including T.Vs) is lower than the rate of duty on the components. For imports under special schemes, such as, advance licensing scheme or imports by 100 per cent Export Oriented Units or units in Free Trade Zone/Export Processing Zone, import of raw materials is permitted duty free for use in the manufacture of products for export. The Government have no specific information about the import duty regime operating in respect of raw matedials in other TV manufacturing countries.

अतिरिक्त शेयर बाजारों के संबंध में फेरवानी समिति की सिफारिशें

2827. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेरवानी समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी की अतिरिक्त शेयर बाजार स्थापित किए जाने चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं ; और

(ग) फेरवानी समिति की अन्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) श्री एम० जे० फेरवानी की अध्यक्षता में नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना हेतु नीति का सुझाव देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1991 में गठित एक अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि सरकार नई बम्बई, नागपुर, ग्वालियर, चंडीगढ़ और शिमला में पांच अतिरिक्त स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करें। सिद्धान्त रूप में सरकार नई बम्बई में एक राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज की स्थापना के लिए अगस्त, 1991 में पहले ही स्वीकृति प्रदान कर चुकी है । अन्य चार प्रस्तावित एक्सचेंजों की स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की मुख्य जिम्मेदारी प्रवर्तकों की है ।

(ग) अन्य मुख्य सिफारिशें राष्ट्रीय निपटान और समझौता पद्धति, एक केन्द्रीय निक्षेपी न्यास और एक प्रतिभूति सुविधा समर्थन निगम की स्थापनाओं से संबंधित है ।

Nadkarni Committee's Report on securities trading

2828. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India might be forced to reintroduce the system of ready forward trading in securities by banks, albeit in a modified form, in the coming days as reported in the Financial Express of the 8th July, 1992, if so, the details thereof;

(b) by when the Nadkarni Committee Report in this regard is expected to be received by Government and whether before reintroducing/revamping this system Government propose to consult securities trading officials, of various banks, financial services, companies, chiefs of Public Sector Banks, etc.;

(c) whether Government also propose to have a fresh look over the system of appointment of brokers and commission paid to them;

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor; and

(e) in what manner the activities of unscrupulous brokers is proposed to be checked?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Reserve Bank of India (RBI) has informed that they have no proposal at present to reintroduce ready forward deals in securities.

(b) The Nadkarni Committee which has been set up by RBI is expected to submit